दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित तिथि: मार्च 19, 2014

निर्णीत तिथि : मार्च 20, 2014

आप.अ. 310/2012

श्यामबीर

..... अपीलार्थी

के माध्यम से: अधिवक्तागण श्री शिव पांडे के
साथ श्री प्रमोद कुमार दुबे ।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार

.....प्रत्यर्थी

के माध्यम से: श्री लवकेश साहनी, अ.लो.अभि.।
उप.नि. मंजीत कुमार, थाना साउथ
कैंपस।

कोरम:

श्री न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग

न्या. एस.पी.गर्ग

1. इस अपील में चुनौती सत्र मामला सं. 95/11 में दिनांक 05.10.2011 के निर्णय को दी गई है, जो पुलिस स्टेशन धौला कुआं में पंजीकृत प्र.सू.रि. सं. 56/10 से उत्पन्न हुआ था, जिसके द्वारा अपीलकर्ता श्यामबीर को धारा 392 सहपठित धारा 397 भा.दं.सं. के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। दिनांक 10.10.2011 को जारी सजा के आदेश में, उसे धारा 392 भा.दं.सं. के तहत पांच साल के कठोर कारावास और 5,000/- जुर्माना तथा धारा 397 भा.दं.सं. के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों मुख्य सजाएँ एक साथ चलेंगी।

2. अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप यह था कि दिनांक 27.03.2010 को लगभग 11.30 बजे अर्जुन विहार बस स्टैंड, धौला कुआं के निकट उसने तथा उसके साथियों जसवंत और संजय उर्फ अजय ने साझा इरादे से डकैती की तथा निजी बस में यात्रा कर रही निर्मला देवी से उसकी सोने की चेन और सोने के कान के टॉप्स छीन लिए। अपीलकर्ता को पीछा करके कुछ दूरी पर पकड़ा गया और उसके कब्जे से अपराध का हथियार यानी चाकू बरामद किया गया। उसके साथी जसवंत और संजय उर्फ अजय मौके से भागने में सफल रहे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ बरामदगी की गई। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद, उन सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किए गए; उन पर विधिवत आरोप लगाए गए; और विचारण

चलाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि संजय उर्फ अजय की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई और उसके खिलाफ कार्यवाही को 'समाप्त' कर दिया गया। 313 के बयानों में, प्रतिवादी आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया। विचारण न्यायलय ने अपने आक्षेपित निर्णय में श्यामबीर को पहले बताए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया जबकि जसवंत को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने उसे बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती नहीं दी। आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अपील दायर की है।

3. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है और फाइल की जांच की है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायलय ने साक्ष्यों को उसके उचित और सच्चे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा। अपीलकर्ता को केवल धारा 397 भा.दं.सं. की सहायता से दोषी ठहराया गया था। हालांकि, सह-अभियुक्त जसवंत को बरी करने से पता चलता है कि उसका इरादा उसके साथ साझा नहीं था। उसके कब्जे से चोरी की गई वस्तुओं की कोई बरामदगी नहीं हुई। जांच अधिकारी ने पहचान परीक्षण कार्यवाही आयोजित करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया। अपीलकर्ता को पकड़ने वाले सैन्यकर्मियों की जांच नहीं की गई और उसे पेश नहीं किया गया। राज्य के विद्वान अपर.लोक.अभि. ने आग्रह किया कि शिकायतकर्ता, उसके पति और भतीजे ने अपीलकर्ता की पहचान डकैती करने वाले

हमलावरों में से एक के रूप में की है और इस आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं, जो साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है।

4. पुलिस तंत्र तब हरकत में आया जब डेली डेरी (डीडी) सं. 15ए (प्र.अभि.सा.-2/सी) द्वारा थाना धौला कुआं में एक झपटमार की गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी गई और दर्ज की गई। जांच का कार्य सहा.उप.नि.रमेश चंद (अभि.सा.-8) को सौंपा गया, जिन्होंने मौके पर जाकर शिकायतकर्ता निर्मला देवी (प्र.अभि.आ.-1/ए) का बयान दर्ज करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। अपनी शिकायत में निर्मला देवी ने घटना का विस्तृत विवरण दिया कि कैसे और किन परिस्थितियों में बस में सवार हमलावरों ने चाकू का इस्तेमाल करके उनकी सोने की चेन और कान की बालियाँ लूट लीं। उन्होंने यह भी बताया कि हमलावरों में से दो मोटरसाइकिल पर भागने में सफल रहे और अपीलकर्ता को एक सैन्यकर्मी ने पकड़ लिया। उसने उसके पास से चाकू बरामद होने की बात भी बताई। न्यायालय में पेश होने के दौरान उसने पुलिस को पहले बताए गए बयान को बिना किसी बदलाव के साबित कर दिया। उसने श्यामबीर को हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना और उसकी भूमिका को विशेष बताया। उसने गवाही दी कि आरोपी संजय ने उसकी पहनी हुई सोने की चेन को छुआ और उसे छीन लिया। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की, तो श्यामबीर (अपीलकर्ता) ने चाकू निकाल लिया और उसे आवाज़ न उठाने की धमकी दी। संजय ने भागते समय उसके सोने के कानों

के टॉप्स भी ले लिए। इसके बाद, संजय और श्यामबीर पिछले गेट से बस से उतर गए और तीसरे हमलावर ने ड्राइवर से बस चलाते रहने को कहा। उसने आगे बताया कि श्यामबीर को घटनास्थल के पास चाकू के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने आते ही उसका बयान (प्र.अभि.सा.-1/ए) दर्ज कर लिया। उसने चाकू (प्र.अभि.1) को अपराध के हथियार के रूप में पहचाना। आरोपी द्वारा उससे जिरह की गई। हालाँकि, उसके बयान पर अविश्वास करने के लिए कोई मूल विसंगति नहीं निकाली जा सकी। गवाह द्वारा बताए गए सभी भौतिक तथ्य अविवादित और निर्विवाद रहे। उसे चोटें आईं और चिकित्सा विधिक मामला (प्र.नया.सा.1/ए) द्वारा डॉ. मुकेश नंदन (न्या.सा.-1) द्वारा उसकी मेडिकल जांच की गई, जिसमें चोटों की प्रकृति को 'साधारण' बताया गया। आरोपी ने चाकू के साथ मौके पर खुद को पकड़े जाने और उस पर लगाए गए आरोप से इनकार नहीं किया।

5. अभि.सा.3 (जगदीश प्रसाद-उसका पति) और अभि.सा.-6 (विनय कुमार तिवारी) जो उक्त बस में यात्रा कर रहे थे, ने बिना किसी विचलन के उसके बयान की पूरी तरह पुष्टि की। उन्होंने श्यामबीर की पहचान हमलावरों में से एक के रूप में की, जिसने चाकू का इस्तेमाल करके धमकी दी, जबकि उसके साथियों ने शिकायतकर्ता से उसके कीमती सामान लूट लिए। उन्होंने घटनास्थल पर घटना के तुरंत बाद चाकू के साथ उसकी गिरफ्तारी को भी साबित कर दिया। फिर से, उनकी जिरह से अपीलकर्ता को लाभ पहुंचाने वाला कोई सार्थक परिणाम नहीं

निकला। इनमें से किसी भी गवाह को, जो अपीलकर्ता से पहले से परिचित नहीं था, उसे झूठा फंसाने और उसकी पहचान करने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं बताया गया। अपीलकर्ता को पकड़ने में सहायक रहे सैन्यकर्मियों से पूछताछ न किए जाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसे उन महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा बिना किसी झिझक के पहचान लिया गया है, जिनका बस के अंदर उससे सीधा सामना हुआ था। साक्ष्य के अभाव और जांच में चूक के कारण सह-अभियुक्त जसवंत को बरी करना अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने के लिए अप्रासंगिक है, जिसे हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना गया है और जिसने सह-अभियुक्तों द्वारा डकैती को अंजाम देने में मदद की थी। आरोपी से बरामद चाकू (प्र.अभि 1) एक बटनदार चाकू था; शस्त्र अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित हथियार। इसके स्केच (प्र.अभि.सा.-3/ए) से इसका आकार और आयाम पता चलता है। जाहिर है, यह डकैती करते समय इस्तेमाल किया जाने वाला एक 'घातक' हथियार था। आरोपी ने अपने खिलाफ जाहिर अपराधिक परिस्थितियों के बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने प्रासंगिक समय पर बस के अंदर चाकू के साथ अपनी उपस्थिति के बारे में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। चूंकि अपीलकर्ता को घटना के तुरंत बाद मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए शनाख्त परीक्षण कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही सुसंगत है और उन्होंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक दूसरे की पुष्टि की

है। किसी भी पूर्व दुश्मनी या दुर्भावना के अभाव में उनके निर्णायक साक्ष्य पर अविश्वास करने और उसे खारिज करने जैसा कुछ भी नहीं है। धारा 397 भा.दं.सं. की सहायता से धारा 392 के तहत अपीलकर्ता की सजा में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और इसकी पुष्टि की जाती है। सजा के आदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 397 भा.दं.सं. के तहत न्यूनतम सजा सात साल है। हालांकि, जुर्माना अदा न करने पर विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को अपीलकर्ता की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ हद तक संशोधित किया जा सकता है।

6. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, धारा 392 के सहपठित धारा 397 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सजा आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि 5,000/- रुपये का जुर्माना अदा न करने पर सजा तीन महीने के स्थान पर पन्द्रह दिन होगी। सजा आदेश के अन्य नियमों और शर्तों को अबाधित छोड़ दिया गया है।

7. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

मार्च 20, 2014
एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।